

दिल्ली राजपत्र

Delhi Gazette



असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 75]	दिल्ली, शुक्रवार, मई 5, 2006/वैशाख 15, 1928	[स.उ.रा.क्षे.दि. सं. 28
No. 75]	DELHI, FRIDAY, MAY 5, 2006/VAISAKHA 15, 1928	[N.C.T.D.No. 28

भाग—IV
PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

भूमि व भवन विभाग
अधिसूचना
दिल्ली, 5 मई, 2006

सं. एफ. 9(95)/2004/भू. व भ./भू. अ./1392.—जबकि दिल्ली के उपराज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि सार्वजनिक प्रयोजन एवं सार्वजनिक व्यय पर सरकार द्वारा दिल्ली के योजनाबद्ध विकास हेतु भूमि प्राप्त किया जाता है। अतः इसके द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि निम्नलिखित इलाके में उक्त प्रयोजन के लिए भूमि अधिग्रहण किया जाना संभावित है।

यह अधिसूचना भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 की धारा 4 के उप-धारा (1) के उपबन्धों के अधीन सर्वसंबंधित के लिए प्रचालित की जाती है।

पूर्वोक्त धारा में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिल्ली के उपराज्यपाल तत्समय कार्यरत अधिकारियों को उनके कर्मचारियों और कामगारों सहित इलाके में किसी भी भूमि में प्रवेश करने व सर्वेक्षण करने और उक्त धारा द्वारा अपेक्षित या अनुमति प्राप्त सभी अन्य कार्य करने के लिए सहर्ष प्राधिकृत करते हैं।

उपराज्यपाल इससे भी संतुष्ट हैं कि उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (1) के उपबंध इस भूमि पर लागू है, उक्त धारा की उप-धारा (4) के अधीन सहर्ष यह भी निर्देश है कि धारा 5-क के उपबंध लागू नहीं होंगे।

विशिष्ट विवरण

गाँव	कुल क्षेत्र (बीघा-बिस्वा)	खसरा नं.	कुल क्षेत्र (बीघा-बिस्वा)
नांगल राया	0-03	270/1	(0-03)

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश तथा नाम पर,
विजय खन्ना, उप-सचिव (भू.अ.)

LAND AND BUILDING DEPARTMENT
NOTIFICATION
Delhi, the 5th May, 2006

No. F. 9(95)/2004/L&B/LA/1392.—Whereas it appears to the Lt. Governor, Delhi that land is likely to be required to be taken by Government at the public expense for a public purpose namely for Planned Development of Delhi. It is hereby

notified that the land in the locality described below is likely to be acquired for the above purpose.

The notification is made, under the provisions of Sub-section (1) of Section 4 of the Land Acquisition Act, 1894, to all whom it may concern.

In exercise of the powers conferred by the aforesaid Section, the Lt. Governor, Delhi is pleased to authorize the officers for the time being engaged in the undertaking with their servants and workmen to enter upon and survey the land in the locality and do all other acts required or permitted by that section.

The Lt. Governor, Delhi is satisfied also that provisions of Sub-section (1) of Section 17 of the said Act are applicable to this land and is further pleased under Sub-section (4) of the said section to direct that all the provisions of Section 5(A) shall not apply.

SPECIFICATION

Village	Total Area (Bigha-Biswa)	Khasra No.	Area (Bigha-Biswa)
Nangal Raya	0-03	270/1	(0-03)

By Order and in the Name of the
Lt. Governor of Delhi,
VIJAY KHANNA, Dy. Secy. (LA)

ऊर्जा विभाग

अधिसूचनाएं

दिल्ली, 5 मई, 2006

सं. फा. 11 (93)/2003/ऊर्जा/1153.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 20 फरवरी, 2004 की अधिसूचना सं. फा. यू-11030/2/2003/यू टी एल के साथ पठित विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 152 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल एतद्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के मंडलीय आयुक्त कार्यालय के समस्त उपायुक्तों को उपरोक्त अधिनियम की धारा 152 के उपबंधों के क्रियान्वयन हेतु विद्युत चोरी के अपराधों के प्रशमन हेतु प्राधिकृत अधिकारियों के रूप में नियुक्त करते हैं।

प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा अपराधों के प्रशमन द्वारा इस प्रकार एकत्रित राशि प्रत्येक माह सरकारी खजाने में जमा की जाएगी।

DEPARTMENT OF POWER

NOTIFICATIONS

Delhi, the 5th May, 2006

No. F. 11(93)/2003/Power/1153.—In exercise of the powers conferred by Section 152 of the Electricity Act, 2003 (36 of 2003) read with Government of India, Ministry of Home Affairs Notification F. No. U-11030/2/2003/UTL dated the 20th February 2004, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi, hereby appoints all Deputy Commissioners, Office of the Divisional Commissioner, Government of National Capital of Delhi, as authorized officers for compounding of offences of theft of electricity for implementation of the provisions of Section 152 of the aforesaid Act.

The sums of money, so collected by way of compounding of offences, by the authorized officers will be deposited in the Government Treasury every months.

सं. फा. 11 (93)/2003/ऊर्जा/1154.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 20 फरवरी, 2004 की अधिसूचना सं. फा. यू-11030/2/2003/यू टी एल के साथ पठित विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 127 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल एतद्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के मंडलीय आयुक्त कार्यालय के समस्त अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेटों को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में उक्त अधिनियम की धारा 127 के उपबंधों के क्रियान्वयन हेतु अपीलीय प्राधिकारी के रूप में नियुक्त करते हैं।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से और उनके नाम पर,

हरीश आहूजा, उप सचिव

No. F. 11(93)/2003/Power/1154.—In exercise of the powers conferred by Section 127 of the Electricity Act, 2003 (36 of 2003) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs Notification No. F. U-11030/2/2003/UTL dated the 20th February, 2004, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi, hereby appoints all Additional District

Magistrates, office of the Divisional Commissioner, Government of National Capital Territory of Delhi as Appellate Authority for the implementation of the provisions of Section 127 of the said Act, in the National Capital Territory of Delhi.

By Order and in the Name of the Lt. Governor
of the National Capital Territory of Delhi,

HARISH K. AHUJA, Dy. Secy.

गृह (पुलिस-II) विभाग

आदेश

दिल्ली, 5 मई, 2006

सं. फा. 11 (7)/92/गृह-II/2898/गृह/06/671.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 10 फरवरी, 2006 की अधिसूचना सं. फा. 14017/7/2005-एन आई-3 तथा गैर कानूनी गतिविधियाँ (निवारण) अधिनियम, 1967 (1967 का 37) की धारा 2 के खंड (जे) तथा के साथ पठित धारा 42 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल केन्द्र सरकार के पूर्व अनुमोदन से निदेश देते हैं कि वे शक्तियाँ, जो उक्त अधिनियम की धारा 7 तथा धारा 8 के अन्तर्गत उसके द्वारा प्रयोग किए जाने योग्य हैं, वे स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया (सिमी) जिसे दिनांक 8 फरवरी, 2006 की अधिसूचना सं. का.आ.191(अ) के अनुसार, 13 फरवरी, 2006 के शुद्धि पत्र सं. का.आ. 206(अ) के साथ पठित गृह मंत्रालय केन्द्र सरकार के द्वारा गैर कानूनी संघ घोषित किया गया है, के संबंध में समस्त राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में पुलिस आयुक्त दिल्ली द्वारा प्रयोग की जाएंगी।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,
के. आर. मेंदीरत्ता, उप सचिव

HOME (POLICE-II) DEPARTMENT

ORDER

Delhi, 5th May, 2006

No. F. 11(7)/92/HP-II/2898/Home/06/671.—In exercise of the powers conferred by Section 42 read with clause (j) of section 2 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (37 of 1967) and the Government of India, Ministry of Home Affairs Notification No. F. 14017/7/2005-NI-III dated the 10th February, 2006, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi, with the previous approval of the Central Government, hereby directs that the powers which are exercisable by him under Section 7 and Section 8 of the said Act shall, with immediate effect, be exercised by the Commissioner of Police, Delhi throughout the National Capital Territory of Delhi, in relation to the Students Islamic Movement of India (SIMI), which has been declared by the Central Government to be an unlawful association vide Ministry of Home Affairs, Notification S.O. No. 191(E) dated the 8th February, 2006 read with Corrigendum No. S.O. 206(E) dated the 13th February, 2006.

By Order and in the Name of the Lt. Governor
of the National Capital Territory of Delhi,

K. R. MENDIRATTA, Dy. Secy.

(पुलिस यातायात उपायुक्त का कार्यालय)

अधिसूचना

दिल्ली, 5 मई, 2006

सं. फा. 20/4/2003/ग.पु.-II/2908/गृह/06/672.—क्योंकि वॉल्ड सिटी की तरफ जाने वाले फीडर रोड्स पर भारी व मध्यम मालवाहक वाहनों के चलने के कारण उत्पन्न होने वाली यातायात की भीड़-भाड़ एवं सड़क प्रयोगकर्ताओं की जान को उत्पन्न होने वाले खतरे से बचने के लिए इस क्षेत्र में यातायात को सुचारू रूप से चलाने व सड़क के प्रयोगकर्ताओं की सुरक्षा एवम् सुविधा के लिए यह करना आवश्यक है।

और क्योंकि यातायात की भीड़-भाड़ की इस समस्या के संदर्भ में वॉल्ड सिटी की तरफ जाने वाले फीडर रोड्स पर यातायात को सुचारू रूप से चलाने व सड़क के प्रयोगकर्ताओं की सुरक्षा एवम् सुविधा के लिए यह करना आवश्यक है।

और क्योंकि वॉल्ड सिटी की तरफ जाने वाले फीडर रोड्स पर भारी व मध्यम मालवाहक वाहनों के चलने पर 24 घण्टे के लिए प्रतिबंध लगाना आवश्यक है।

अब मैं, महावीर सिंह, उपायुक्त पुलिस, यातायात (मुख्यालय) दिल्ली, दिल्ली में सड़कों व गलियों पर वाहन व अन्य यातायात नियम, 1980 की धारा 30(1) जिसके अन्तर्गत मुझे अधिकार प्राप्त है, का प्रयोग करते हुये एतद्द्वारा भारी व मध्यम मालवाहक वाहनों को निम्नलिखित मार्गों पर चलने एवं खड़ा करने पर 24 घण्टे के लिए प्रतिबंध लगाता हूँ। अगले आदेश तक :—

1. रोहतक रोड पर पंजाबी बाग फ्लाईओवर से रानी झांसी मार्ग तक।
2. कालीदास मार्ग (के. डी. मार्ग) पर गंदा नाला भरत नगर से कमल टी प्वाइंट रोहतक रोड।

3. रोड नं. 40 पर जखिरा फ्लाईओवर से चाई प्वाइंट किशनगंज।
4. पुलिस स्टेशन सराय रोहिला के सामने वाले रोड पर पुराना रोहतक रोड से के. डी. मार्ग तक।
5. करमपुरा रोड पर पंजाबी बाग, रिंग रोड से मोती नगर क्रॉसिंग तक।
6. पुराना रोहतक रोड पर जखिरा फ्लाईओवर से आजाद मार्किट।
7. नजफगढ़ रोड, रिंग रोड से जखिरा फ्लाईओवर।
8. रामा रोड पर भायापुरी फ्लाईओवर, रिंग रोड से जखिरा फ्लाईओवर तक।

इस कार्यालय की अधिसूचना सं. 6687-6877/या. अधि. शा. (डी-2) दिनांक 4-8-2005 जोकि भारी व मध्यम मालवाहक वाहनों को प्रातः और सांयकाल के व्यस्त समय में उपरोक्त मार्गों पर चलने व खड़ा करने पर प्रतिबंध हेतु थी इस आदेश के बाद निरस्त समझी जाएगी। सामान्य जनता के सूचनार्थ इस आदेश को सरकारी राजपत्र में प्रकाशित किया जायेगा तथा समस्त जिला पुलिस उपायुक्तों तथा तमाम थानों दिल्ली/नई दिल्ली के सूचना पट्टों पर इसकी एक प्रति चिपकाई जायेगी। संबंधित अधिकरण एवम् सड़क रख-रखाव प्राधिकरण जन साधारण को सूचनार्थ एवम् सुविधा हेतु आवश्यक संकेत पट्ट प्रतिबंधित संकेत को इंगित करते हुए लगाएंगे।

यह आदेश दिनांक 05-05-2006 से लागू होगा।

मेरे द्वारा इस कार्यालय की मोहर के साथ दिनांक 05-05-2006 को जारी किया गया।

महाबीर सिंह, उपायुक्त

OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER OF POLICE, TRAFFIC
NOTIFICATION

Delhi, the 5th May, 2006

F. No. 20/4/2003/HP-II/2908/HOME/06/672.—Whereas, it is necessary to ensure smooth flow of traffic, prevent congestion, safety of all road users and inconvenience to general public due to the movement of heavy and medium goods vehicles, which cause traffic problems and congestion and also endanger the life of various road users on the feeder roads leading to walled city.

And whereas, in view of this problem of congestion on the feeder roads leading to walled city and safety all road users, it is necessary to regulate the movement of traffic on the feeder roads leading to walled city for the convenience of general public.

And whereas, it is necessary to prohibit the plying of heavy and medium goods vehicles for 24 hours of the day on the feeder roads leading to walled city.

Now, therefore, I, Mahabir Singh, Deputy Commissioner of Police, Traffic (Hdqs.) Delhi in exercise of the powers conferred upon me under Regulation 30(i) of the Delhi Control of Vehicular and other traffic on Roads and Streets Regulation, 1980 do hereby prohibit the plying and idle parking of heavy and medium goods vehicles for 24 hours of the day on the feeder roads leading to walled city as mentioned below :—

- (a) Rohtak Road from Punjabi Bagh Flyover upto Rani Jhansi Road.
- (b) Kalidas Marg (K.D. Marg) from Ganda Nala Bharat Nagar upto Kamal T-point, Rohtak Road.
- (c) Road No. 40 from Zakhira Flyover upto Y-point Kishanganj.
- (d) Road in front of P. S. Sarai Rohilla from Old Rohtak Road upto K. D. Marg.
- (e) Karampura Road from Punjabi Bagh, Ring Road upto Moti Nagar Crossing.
- (f) Old Rohtak Road from Zakhira Flyover to Azad Market.
- (g) Najafgarh Road, Ring Road to Zakhira Flyover.
- (h) Rama Road from Maya Puri Flyover, Ring Road upto Zakhira Flyover.

This notification supersedes the earlier notification No. 6687-6877/TE (D-II) dated 4-8-2005 issued for prohibiting the plying and idle parking of heavy and medium goods vehicles during the morning and evening peak hours on the above mentioned roads.

This order shall be published for the information of the general public in the Official Gazette and by affixing a copy on the notice boards of the office of all District Deputy Commissioner of Police and all Police Stations in Delhi/New Delhi.

The concerned civic road agencies maintaining the roads/areas shall erect the corresponding signboards indicating the restrictions in the area for information and convenience of all concerned.

This order shall come into force with effect from 05-05-2006.

Given under my hand and seal of this office on the 5th day of May, 2006.

MAHABIR SINGH, Dy. Commissioner

PART XII

INVESTIGATION AND ENFORCEMENT

Section 126: (Assessment): -- (1) If on an inspection of any place or premises or after inspection of the equipments, gadgets, machines, devices found connected or used, or after inspection of records maintained by any person, the assessing officer comes to the conclusion that such person is indulging in unauthorized use of electricity, he shall provisionally assess to the best of his judgement the electricity charges payable by such person or by any other person benefited by such use.

(2) The order of provisional assessment shall be served upon the person in occupation or possession or in charge of the place or premises in such manner as may be prescribed.

¹[(3) The person, on whom an order has been served under sub-section (2) shall be entitled to file objections, if any, against the provisional assessment before the assessing officer, who shall, after affording a reasonable opportunity of hearing to such person, pass a final order of assessment within thirty days from the date of service of such order of provisional assessment of the electricity charges payable by such person.]

(4) Any person served with the order of provisional assessment, may, accept such assessment and deposit the assessed amount with the licensee within seven days of service of such provisional assessment order upon him:

²[***]

³[(5) If the assessing officer reaches to the conclusion that unauthorised use of electricity has taken place, the assessment shall be made for the entire period during which such unauthorized use of electricity has taken place and if, however, the period during which such unauthorised use of electricity has taken place cannot be ascertained, such period shall be limited to a period of twelve months immediately preceding the date of inspection.]

¹ Subs. by Act 26 of 2007, Sec.11 (w.e.f. 15th June 2007).

² The words "Provided that in case the person deposits the assessed amount he shall not be subjected to any further liability or any action by any authority whatsoever" omitted by Act 26 of 2007, Sec.11 (w.e.f. 15th June 2007).

³ Subs. by Act 26 of 2007, Sec.11 (w.e.f. 15th June 2007).

(6) The assessment under this section shall be made at a rate equal to ¹[twice] the tariff rates applicable for the relevant category of services specified in sub-section (5).

Explanation.- For the purposes of this section,-

- (a) "assessing officer" means an officer of a State Government or Board or licensee, as the case may be, designated as such by the State Government;
- (b) "unauthorised use of electricity" means the usage of electricity -
- (i) by any artificial means; or
 - (ii) by a means not authorised by the concerned person or authority or licensee; or
 - (iii) through a tampered meter; or
 - ²[(iv) for the purpose other than for which the usage of electricity was authorised; or
 - (v) for the premises or areas other than those for which the supply of electricity was authorized."]

Section 127. (Appeal to Appellate Authority): --- (1) Any person aggrieved by the final order made under section 126 may, within thirty days of the said order, prefer an appeal in such form, verified in such manner and be accompanied by such fee as may be specified by the State Commission, to an appellate authority as may be prescribed.

(2) No appeal against an order of assessment under sub-section (1) shall be entertained unless an amount equal to ³[half of the assessed amount] is deposited in cash or by way of bank draft with the licensee and documentary evidence of such deposit has been enclosed along with the appeal.

(3) The appellate authority referred to in sub-section (1) shall dispose of the appeal after hearing the parties and pass appropriate order and send copy of the order to the assessing officer and the appellant.

(4) The order of the appellate authority referred to in sub-section (1) passed under sub-section (3) shall be final.

¹ subs. by Act 26 of 2007, Sec. 11 for the words "one-and-half times" (w.e.f. 15th June 2007).

² Subs. by Act 26 of 2007, Sec. 11 (w.e.f. 15th June 2007)

³ Subs. by Act 26 of 2007, Sec.12 for the words "one third of the assessed amount" (w.e.f. 15th June 2007).

(5) No appeal shall lie to the appellate authority referred to in sub-section (1) against the final order made with the consent of the parties.

(6) When a person defaults in making payment of assessed amount, he, in addition to the assessed amount shall be liable to pay, on the expiry of thirty days from the date of order of assessment, an amount of interest at the rate of sixteen per cent, per annum compounded every six months.

Section 128. (Investigation of certain matters): --- (1) The Appropriate Commission may, on being satisfied that a licensee has failed to comply with any of the conditions of licence or a generating company or a licensee has failed to comply with any of the provisions of this Act or rules or regulations made thereunder, at any time, by order in writing, direct any person (hereafter in this section referred to as "Investigating Authority") specified in the order to investigate the affairs of any generating company or licensee and to report to that Commission on any investigation made by such Investigating Authority:

Provided that the Investigating Authority may, wherever necessary, employ any auditor or any other person for the purpose of assisting him in any investigation under this section.

(2) Notwithstanding anything to the contrary contained in section 235 of the Companies Act, 1956, the Investigating Authority may, at any time, and shall, on being directed so to do by the Appropriate Commission, cause an inspection to be made, by one or more of his officers, of any licensee or generating company and his books of account; and the Investigating Authority shall supply to the licensee or generating company, as the case may be, a copy of his report on such inspection.

(3) It shall be the duty of every manager, managing director or other officer of the licensee or generating company, as the case may be, to produce before the Investigating Authority directed to make the investigation under sub-section (1), or inspection under sub-section (2), all such books of account, registers and other documents in his custody or power and to furnish him with any statement and information relating to the affairs of the licensee or generating company, as the case may be, as the said Investigating Authority may require of him within such time as the said Investigating Authority may specify.

(4) Any Investigating Authority, directed to make an investigation under sub-section (1), or inspection under sub-section (2), may examine on oath any manager, managing director or other officer of the licensee or generating company, as the case may be, in relation to his business and may administer oaths accordingly.

section 137, or section 138, on his conviction for such abetment, may also be cancelled by the licensing authority:

Provided that no order of such cancellation shall be made without giving such person an opportunity of being heard.

Explanation.- For the purposes of this sub-section, "licencing authority" means the officer who for the time being in force is issuing or renewing such licence or certificate of competency or permit or such other authorisation.]

Section 151. (Cognizance of offences):

No court shall take cognizance of an offence punishable under this Act except upon a complaint in writing made by Appropriate Government or Appropriate Commission or any of their officer authorized by them or a Chief Electrical Inspector or an Electrical Inspector or licensee or the generating company, as the case may be, for this purpose.

¹[Provided that the court may also take cognizance of an offence punishable under this Act upon a report of a police officer filed under section 173 of the Code of Criminal Procedure, 1973:

Provided further that a special court constituted under section 153 shall be competent to take cognizance of an offence without the accused being committed to it for trial.]

²[151A. For the purposes of investigation of an offence punishable under this Act, the police officer shall have all the powers as provided in Chapter XII of the Code of Criminal Procedure, 1973.

151B. Notwithstanding anything contained in the Code of Criminal Procedure, 1973, an offence punishable under sections 135 to 140 or section 150 shall be cognizable and non-bailable.]

Section 152. (Compounding of offences): --- (1) Notwithstanding anything contained in the Code of Criminal Procedure 1973, the Appropriate Government or any officer authorized by it in this behalf may accept from any consumer or person who committed or who is reasonably suspected of having committed an offence of theft of electricity punishable under this Act, a sum of money by way of compounding of the offence as specified in the Table below:

¹ Ins. by Act 26 of 2007, Sec.15 (w.e.f. 15th June 2007).

² Ins. by Act 26 of 2007, Sec.16 (w.e.f. 15th June 2007).

TABLE

Nature of Service	Rate at which the sum of money for Compounding to be collected per Kilowatt(KW)/Horse Power(HP) or part thereof for Low Tension (LT) supply and per Kilo Volt Ampere(KVA) of contracted demand for High Tension (HT)
(1)	(2)
1. Industrial Service	twenty thousand rupees;
2. Commercial Service	ten thousand rupees;
3. Agricultural Service	two thousand rupees;
4. Other Services	four thousand rupees:

Provided that the Appropriate Government may, by notification in the Official Gazette, amend the rates specified in the Table above.

(2) On payment of the sum of money in accordance with sub-section (1), any person in custody in connection with that offence shall be set at liberty and no proceedings shall be instituted or continued against such consumer or person in any criminal court.

(3) The acceptance of the sum of money for compounding an offence in accordance with sub-section (1) by the Appropriate Government or an officer empowered in this behalf shall be deemed to amount to an acquittal within the meaning of section 300 of the Code of Criminal Procedure, 1973.

(4) The Compounding of an offence under sub-section (1) shall be allowed only once for any person or consumer.